books were stolen some time back from the Slavonic Division of National Library, Calcutta;

(b) whether it is also a fact that though the culprit was caught red-handed nothing has been done to retrieve the books;

(c) whether it is a fact that some valuable periodicals were also stolen from the Library; and

(d) whether any enquiry Committee has been set up to investigate these thefts and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Four books from the Slavonic Languages Division and 51 books from the Romance Languages Division were stolen.

(b) No, Sir. The culprit was caught and the books were retrieved from his residence.

(c) Yes, Sir. Three issues of periodicals were stolen.

(d) No, Sir. No action could be taken against the culprit because he committed suicide on 21st October, 1991.

दिल्ली विकास प्राधिकरण में अधिशेष कर्मचारी

*257. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :

श्री राम सिंह राठवा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्यरत फालतू कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन फालतू कर्मचारियों को प्रतिमाह कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितना वार्षिक आर्थिक बोझ वहन करना पड़ रहा है ;

(ग) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार फालतू कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को क्या निर्देश जारी किये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि केवल समूह "ख" (नियमित) श्रेणी में 1124 बेशी कर्मचारी हैं । अन्य किसी श्रेणी में कोई बेशी कर्मचारी नहीं है ।

(ख) बेशी कर्मचारियों को लगभग 22.48 लाख रुपये मासिक अर्थात् 2.70 करोड़ रुपये वार्षिक राशि दी जाती है ।

(ग) सी०ए०जी० रिपोर्ट के अनुसार 1989-90, 1990-91 और 1991-92 वर्षों में समूह "ख" में वास्तविक कर्मचारी संख्या स्वीकृत कर्मचारी संख्या से काफी अधिक रही है । ये अधिशेष 75 से 83% के बीच था ।

बेशी कर्मचारियों (नियमित) के 30 जून, 1993 को ब्यौरे इस प्रकार है :—

स्वीकृत कर्मचारी	2536
कार्यरत	3660
बेशी	1124

(घ) भारत सरकार ने 21 फरवरी, 1992 को दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये हैं कि समूह "क", "ख" तथा "ग" में कतिपय रिक्त पद न भरे जाएं, समूह "ग" के 460 रिक्त पदों को समाप्त कर दिया जाए, समूह "घ" के 550 पदों को क्रमशः खाली होने पर समाप्त करने की प्रक्रिया अपनायी जाए, 230 कालोनियों को, उनके नाम पर कार्यरत लगभग 3500 कर्मचारियों सहित, दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया जाए ।

Built up Area in Raj Nagar, Palam Colony

*258. SHRI RATNA BAHADUR RAI : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for de-notification of acquired and built-up area of Raj Nagar Part-II, Palam Colony, New Delhi for the purview of the award of acquisition; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SMT. SHEILA KAUL) : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

Illegal Occupation of a Khasra in Village Ladho Sarai

*259. SHRI JAGMOHAN : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Khasra No. 166 measuring about 46 Bighas in the village Ladho Sarai in Mehrauli belongs to the D. D. A.;

(b) whether the land use of this area is green and is very near the Qutab Minar and other historical monuments;

(c) whether this land is being illegally/unauthorisedly developed/sold in total violation of the laws on the subject;

(d) whether it has come to the notice of the

Government that some influential persons are purchasing plots in the aforesaid area; and

(e) what action has been taken to prevent illegal sale/colonisation/construction and whether Government propose to put up a special picket to keep watch over the area?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SMT. SHEILA KAUL): (a) As reported by DDA, the title of 46 bighas 9 biswas of land bearing Khasra No. 166 of village Ladho Sarai is sub-judice in the High Court of Delhi.

(b) The prescribed land use of the land is "recreational".

(c) and (d) The Deputy Commissioner, Delhi has reported that unauthorised development and sale/purchase of the land is taking place.

(e) The DDA has issued a public notice warning the public that the sale/purchase of this piece of land is illegal till the matter is finalised by the Competent court. It is also keeping a watch on the area.

मसालों के लिए समर्थन-मूल्य

*260. **श्री कैलाश नारायण सारंग**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि किसानों को लहसुन, धनिया और मिर्च आदि मसालों की फसलों के लिए उपयुक्त मूल्य नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन फसलों के लिए भी समर्थन मूल्य निर्धारित करने पर विचार करेगी, जैसाकि खाद्यान्नों, दालों और तिलहनों के संबंध में किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) वर्ष 1993 में सामान्यतया: मसालों तथा विशेषकर लहसुन, धनिया और लाल मिर्च के थोक मूल्यों में समझ और अन्तराल की दृष्टि से उतार-चढ़ाव आया है जैसाकि व्यावहारिक रूप से सभी कृषि जिंसों के मामले में हुआ है। यह उतार-चढ़ाव मुख्यतया इन जिंसों की मांग और आपूर्ति, विदेशी उत्पादन तथा निर्यात में अंतर के कारण आया है। यद्यपि 1993 में लाल मिर्च के थोक मूल्य नरम रहे, तथापि लहसुन और धनिया के थोक मूल्य कुल मिलाकर 1992 के स्तर से अधिक रहे।

(ख) और (ग) विभिन्न फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत लाने के प्रश्न को कृषि लागत और मूल्य आयोग से परामर्श करते हुए लगातार समीक्षा की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में शामिल की जाने वाली फसलों के बारे में निर्णय लेते समय स्थानिक उत्पादन वाली और देश में व्यापक रूप से उगायी जाने वाली फसलों, जल्द खराब होने वाली तथा जल्द खराब न होने वाली कृषि जिंसों और देश के कुल फसल उत्पादन में योगदान देने वाली फसलों में अन्तर करने का प्रयास किया जाता है। मसालों के मामले में, इनमें से कोई भी मानदण्ड उन्हें न्यूनतम समर्थन योजना में शामिल किए जाने के लिए उचित नहीं ठहराता। लेकिन, यदि मूल्य अलाभकारी स्तर तक गिर जाएं तो राज्य सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर मसालों को मंडी में हस्तक्षेप करने की योजना के अंतर्गत लाया जा रहा है।

Role of Animal in Agricultural Operation

2249. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that animal power plays a great role in the agricultural operations of the country;

(b) whether Government have assessed the importance of animal power in agricultural operation; if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that number of animals in the country is gradually coming down;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the steps being taken to check this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Yes, Sir.

(b) On an average a pair of bullocks is capable to manage 3 hectares. On this basis, the crop area which can be managed by 40 million pairs of bullocks is 120 M hect., out of total sown area of 150 M hect. By 2000 AD the requirement may remain the same because of better breed and better health. So number is to be maintained at existing level.

(c) No, Sir. The Cattle population according to 1982 Census was 192.45 Million and it has increased to 199.45 million in 1987.

(d) Does not arise.

(e) Does not arise.

दालों और मसालों का उत्पादन

2250. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो/तीन वर्षों के दौरान